

### अध्याय III: वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान मंत्रालय

#### सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

#### परिचालनों के सम्पन्न पर अनुत्पादक व्यय

सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसके सोलर फोटोवोल्टेयिक संयंत्र के परिचालनों को दो मेगावाट पीक से 10 मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी) प्रति वर्ष तक सम्पन्न किया। तथापि, सोलर फोटोवोल्टेयिक सैल का उत्पादन 2007-08 से 2014-15 के दौरान दो एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष की मूल क्षमता से भी नीचे रहा जिसने परिचालनों को सम्पन्न करने पर ₹ 22.43 करोड़ के व्यय को व्यर्थ बना दिया।

सेन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कम्पनी) का साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में एक सोलर फोटोवोल्टेयिक (एसपीवी) प्लांट सिलिकॉन वेफर के प्रक्रमण द्वारा एसपीवी सैल बनाने के लिए है। संयंत्र की क्षमता एक अद्यतन एवं सम्पन्नन परियोजना के अन्तर्गत दो मेगावाट पीक<sup>1</sup> (एमडब्ल्यूपी) प्रतिवर्ष से 10 एमडब्ल्यूपी प्रतिवर्ष बढ़ाई गई थी तथा सम्पन्न परियोजना ₹ 22.43 करोड़ की कीमत पर जुलाई 2007 में सम्पूर्ण हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संयंत्र का उपयोग 2007-08 से 2014-15 के दौरान 0.25 एमडब्ल्यूपी से 1.30 एमडब्ल्यूपी के मध्य की क्षमता पर प्रयोग किया जा रहा था। संयंत्र की क्षमता प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दी गई थी कि दो एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष की तत्कालीन पर उत्पादन मात्रा उत्पादन खर्च तथा ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी तथा कम्पनी केवल तभी घरेलू तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती है यदि यह इसके वर्तमान संयंत्र क्षमता को न्यूनतम 10 एमडब्ल्यूपी तक बढ़ाती। तथापि, पिछले आठ वर्षों में वास्तविक क्षमता प्रयोग दो एमडब्ल्यूपी की मूल क्षमता से भी कम था जिसने संयंत्र के सम्पन्न होने पर ₹ 22.43 करोड़ के सम्पूर्ण खर्च को व्यर्थ बना दिया।

कम उत्पादन के कारणों के संबंध में प्रबंधन का तर्क (अगस्त 2011) था कि सिलिकॉन वेफर के बाजार में अस्थिरता के कारण, कम्पनी ने सिलिकॉन वेफर का सैलो में रूपान्तरण को कम करने तथा सैलो को (बाहर से उपार्जित) सौर माड्यूलों में रूपान्तरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने का निर्णय लिया क्योंकि वह अधिक लाभदायक पाई गई।

<sup>1</sup> 1000 किलो वाट पीक, एक मेगावाट पीक के समान है।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच (अप्रैल 2014) से पता चला कि सिलिकॉन वेफर की मांग तथा उत्पादन पर विचार करते समय कम्पनी ने कच्चे माल (यथा सिलिकान वेफर) की उपलब्धता तथा इसकी प्राप्ति के स्रोत की वास्तविक स्थिति पर विचार नहीं किया था वास्तव में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (नवम्बर 2003) में केवल यही कहा कि सिलिकॉन बहुत मात्रा में उपलब्ध था क्योंकि यह पृथ्वी की भूपर्पटी के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों ने इंगित किया कि कम्पनी इस तथ्य से अभिज्ञ था कि सिलिकॉन माल तथा वेफर के लिए मांग 2004 में ही भारत में कुल उत्पादन से अधिक हो गया था तथा भारतीय फोटोवोल्टेयिक उद्यम के लिए सिलिकॉन वेफर की लगभग 90 प्रतिशत आवश्यकता आयातों के माध्यम से पूरी होती है। तथपि भारत सरकार ने सौर फोटोवोल्टेयिक परिचालनों के 29 मार्च 2005 को 10 एमडब्ल्यूपी प्रति वर्ष तक उन्नयन तथा सम्पन्न होने को स्वीकृत किया।

प्रबंधन ने आगे कहा (अप्रैल 2014) कि चूंकि सैलो के उत्पादन की कीमत प्रचलित बाजार मूल्य से बहुत ऊंची थी तथा निजी भागीदारों से प्रतिस्पर्धा थी, उत्पादन को और घाटे से बचने के लिए नहीं बढ़ाया गया था।

प्रबंधन का तर्क परिचालनों को सम्पन्न करने के लिए प्रस्ताव को उचित ठहरने के लिए इसकी पहले तर्क के प्रतिकूल है, जिसमें इसने कहा था कि उत्पादन क्षमता में व्यापक वृद्धि में बढ़त ही उत्पादन की उच्च लागत को कम कर सकती है।

इस प्रकार, कम्पनी ने कच्चे माल की उपलब्धता में अवरोधों तथा वेफर के बाजार में अस्थिरता के प्रकाश में परियोजना की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था। इसने ₹ 22.43 करोड़ के सम्पूर्ण व्यय को व्यर्थ बना दिया क्योंकि परिचालनों के सम्पन्न होने के बाद क्षमता प्रयोग मूल क्षमता से भी निम्नतर रखा गया था।

मामले को अक्टूबर 2015 को मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2016) था।